



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2172]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939

No. 2172]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

का.आ. 2472(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4116(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2016, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 22 दिसम्बर, 2016 के प्रकाशित होने पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमियों और ऐसी भूमियों में या उस पर के सभी अधिकार (जिसे इसमें पश्चात् उक्त भूमियों कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए तैयार है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि 64.43 हेक्टेयर (लगभग) या 159.20 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 22 दिसम्बर, 2016 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे अर्थात् :-

- (1) सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम, के उपबन्धों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों के बाबत् सभी संदाय विद्युत मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
- (2) सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त कम्पनी द्वारा वहन किये जाएंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकारों के लिए या उसके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों, जिसके अंतर्गत अपील या अन्य कार्यवाहियां भी हैं, के संबंध में, उपगत, सभी व्यय भी, इसी प्रकार उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जाएंगे;

- (3) सरकारी कम्पनी केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों के, ऐसे अन्य व्ययों की भी, क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आवश्यक हों;
- (4) सरकारी कम्पनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमियों और उक्त भूमि में या उसके पर के अधिकारों को, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- (5) सरकारी कम्पनी, ऐसे निदेशों और शर्तों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं, पालन करेगी।

[फा. सं. 43015/1/2016-एलए एण्ड आईआर/खंड-II]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2017

S.O. 2472(E).—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 4116(E), dated the 21st December, 2016 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2016 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) the lands and all rights in or over such lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the NTPC Limited, New Delhi, a Public Sector undertaking under the Ministry of Power (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the lands measuring 64.43 hectares (approximately) or 159.20 acres (approximately) and all rights in or over such lands so vested, shall with effect from the 22nd December, 2016, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (1) The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made by the Central Government through Ministry of Power in respect of compensation, interest, damages and the like as determined under the provisions of the said Act;
- (2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals or other proceedings for or in connection with rights in or over the said lands so vested, shall also be borne by the Government Company;
- (3) The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;
- (4) The Government Company shall have no power to transfer the said lands and the rights in or over the said lands to any other person without the prior approval of the Central Government; and
- (5) The Government Company shall comply with such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular area of the said lands as and when necessary.

[F. No. 43015/1/2016-LA&IR/Vol.- II]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.